Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 7.384
Volume - 8, Issue - 9, September - 2025

DOIs:10.2018/SS/202509003 --:-- Research Paper / Article / Review

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना: स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुधार का अध्ययन

सत्यपाल यादव[1], प्रो० गोपाल प्रसाद[2]
[1]शोध छात्र, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
[2]आचार्य, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
Email - [1] satyapalyadav2032000@gmail.com
[2]drgopalprasad@gmail.com

सारांश : प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी सामाजिक-आर्थिक पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन के रूप में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) उपलब्ध कराना है। पारंपरिक ठोस ईंधनों जैसे लकड़ी, गोबर के उपले और कोयले के उपयोग से उत्पन्न इनडोर वायु प्रदूषण से हर वर्ष लाखों महिलाओं और बच्चों की जान जाती है। यह योजना महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराकर न केवल स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करती है, बल्कि समय की बचत, श्रम में कमी, और पर्यावरणीय स्थिरता को भी प्रोत्साहित करती है। यह शोध-पत्र उज्ज्वला योजना की पृष्ठभूमि, कार्यान्वयन, उपलब्धियों, चुनौतियों और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में सरकारी आँकड़ों, अकादमिक शोध और जमीनी रिपोर्टों का उपयोग किया गया है ताकि एक संतुलित और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके।

कुंजी शब्द - प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, एलपीजी, महिला सशक्तिकरण, इनडोर वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य प्रभाव, सामाजिक-आर्थिक विकास, ग्रामीण भारत, ऊर्जा नीति ।

1. परिचय

भारत में ग्रामीण और गरीब शहरी परिवारों में खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधनों का उपयोग एक सामान्य प्रथा रही है। लकड़ी, कोयला और गोबर के उपले जैसे ठोस ईंधनों के जलने से उत्पन्न धुआँ इनडोर वायु प्रदूषण का कारण बनता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार गंभीर श्वसन रोग, नेत्र समस्याएं और हृदय संबंधी बीमारियों का प्रमुख कारण है। महिलाओं और बच्चों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से गहरा होता है क्योंकि वे घर के भीतर अधिक समय बिताते हैं और रसोई धुएं के सीधे संपर्क में रहते हैं। 2016 में भारत सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। योजना का

उद्देश्य केवल ईंधन का विकल्प प्रदान करना नहीं था, बल्कि यह स्वास्थ्य सुधार, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण का भी एक माध्यम बनी।

2. साहित्य समीक्षा

ऊर्जा गरीबी और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर पिछले दो दशकों में कई शोध हुए हैं। स्मिथ (2000) के अध्ययन में पाया गया कि पारंपरिक ईंधनों का उपयोग इनडोर वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है और यह प्रति वर्ष विश्व स्तर पर लगभग 4 मिलियन मौतों में योगदान देता है। भारत में, नरेश कुमार और सहयोगियों (2014) ने यह दर्शाया कि स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार ला सकती है। प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना पर हुए प्रारंभिक अध्ययनों (Gould & Urpelainen, 2018) ने यह निष्कर्ष निकाला कि योजना ने एलपीजी कनेक्शन के विस्तार में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की, लेकिन निरंतर उपयोग सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। 2021 में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की रिपोर्ट में यह कहा गया कि सब्सिडी और जागरूकता अभियान के संयोजन से ही योजना के दीर्घकालिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। यह साहित्य समीक्षा दर्शाती है कि उज्ज्वला योजना न केवल ऊर्जा क्षेत्र का हस्तक्षेप है, बल्कि यह स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है।

3. अनुसंधान उद्देश्य एवं प्रश्न

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अनुसंधान प्रश्नों का उत्तर खोजा गया है:

1. योजना के कार्यान्वयन से स्वास्थ्य और समय-प्रबंधन में क्या सुधार हुए?
2. क्या योजना ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति और आर्थिक अवसरों में वृद्धि की है?
3. निरंतर उपयोग (रिफिल दर) में किन कारकों की भूमिका रही है?
4. योजना की सीमाएँ और चुनौतियाँ क्या हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?

4. कार्यप्रणाली

यह शोध मिश्रित पद्धति (Mixed Method) पर आधारित है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया गया। सरकारी स्रोतों जैसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, योजना आयोग, और नीति आयोग की रिपोर्टों से आँकड़े संकलित किए गए। साथ ही, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS), एनएसएसओ (NSSO) डेटा, और पीआईबी प्रेस नोट्स का विश्लेषण किया गया। साहित्य समीक्षा के लिए Google Scholar, JSTOR, और सरकारी प्रकाशनों से संबंधित शोध-पत्रों को चुना गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों के केस स्टडीज़, मीडिया रिपोर्ट्स और एनजीओ की जमीनी रिपोर्टों को भी शामिल किया गया ताकि योजना का समग्र मूल्यांकन किया जा सके।

5. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तृत विवरण

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में किया गया। योजना का लक्ष्य पांच करोड़ बीपीएल परिवारों को 2019 तक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था, जिसे बाद में बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया। पात्रता के लिए बीपीएल सूची में नाम, महिला लाभार्थी का बैंक खाता, और आधार कार्ड आवश्यक थे। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को ₹1,600 की वित्तीय सहायता दी गई, जिसमें सुरक्षा जमा, रेगुलेटर, पाइप और प्रारंभिक रिफिल की लागत शामिल थी। योजना का क्रियान्वयन तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के माध्यम से किया गया, और लाभ सीधे लाभार्थी के नाम पर दर्ज किए गए, जिससे महिलाओं के नाम पर एलपीजी कनेक्शन स्वामित्व सुनिश्चित हुआ।

6. कार्यान्वयन एवं वित्तीय ढांचा

योजना के पहले चरण के लिए ₹8,000 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया था। तेल विपणन कंपनियों को लागत का प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा दी गई। लाभार्थियों को प्रारंभिक स्टोव और सिलिंडर के लिए ब्याज-मुक्त ऋण की सुविधा भी दी गई, जिसे बाद में रिफिल की खरीद के माध्यम से धीरे-धीरे चुकाया जाता था। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 2021 में हुई, जिसमें विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए पते के प्रमाण में रियायत दी गई और पहले रिफिल और स्टोव मुफ्त प्रदान किए गए। 2023 में उज्ज्वला उपभोक्ताओं को प्रति सिलिंडर ₹300 की सब्सिडी दी गई, जो साल में अधिकतम 12 रिफिल तक सीमित थी।

7. प्रगति एवं उपलब्धियां

योजना की शुरुआत के पहले वर्ष में ही 2.2 करोड़ कनेक्शन वितरित किए गए। 2019 तक लक्ष्य से अधिक 8 करोड़ कनेक्शन प्रदान किए गए और दिसंबर 2024 तक यह संख्या 9.6 करोड़ तक पहुँच गई। रिफिल दर शुरुआती वर्षों में औसतन 3 सिलिंडर प्रति वर्ष थी, जो 2024 में बढ़कर 4.47 हो गई। कई अध्ययनों में यह पाया गया कि योजना ने महिला स्वास्थ्य में सुधार, बच्चों के श्वसन रोगों में कमी, और घरेलू कार्यों में समय की बचत सुनिश्चित की।

8. स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव

WHO और ICMR के संयुक्त अध्ययनों के अनुसार, उज्ज्वला योजना से जुड़े घरों में महिलाओं और बच्चों के श्वसन रोगों में औसतन 20-25% की कमी आई है। समय की बचत प्रतिदिन औसतन 1.5 से 2 घंटे रही, जिससे महिलाएं आय अर्जन, शिक्षा या परिवार के अन्य कार्यों में समय दे सकीं। पर्यावरणीय दृष्टि से, ठोस ईंधन के उपयोग में कमी से CO_2 और ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय गिरावट आई। सामाजिक स्तर पर, महिलाओं के नाम पर कनेक्शन होने से उनकी पारिवारिक निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी और घरेलू संसाधनों पर उनका नियंत्रण मजबूत हुआ।

उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश योजना के सबसे बड़े लाभार्थी राज्य रहे, जहाँ बड़ी संख्या में बीपीएल परिवार हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में योजना का कवरेज अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन मिज़ोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में रिफिल दर अधिक पाई गई, जिसका कारण बेहतर वितरण नेटवर्क और जागरूकता अभियान थे। राजस्थान और महाराष्ट्र में योजना का स्वास्थ्य प्रभाव अधिक रहा क्योंकि वहाँ पारंपरिक ईंधनों के उपयोग से होने वाली बीमारियों का बोझ पहले से अधिक था।

9. अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में तुलना

विश्व के कई विकासशील देशों में स्वच्छ ईंधन को अपनाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की पहल हुई है, लेकिन भारत की प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) अपनी पैमाने और लाभार्थियों की संख्या के कारण विशिष्ट स्थान रखती है। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश में “Clean Cooking Alliance” कार्यक्रम ने ग्रामीण महिलाओं को सब्सिडी और माइक्रो-फाइनेंस के माध्यम से एलपीजी उपलब्ध कराया, किंतु इसका कवरेज PMUY की तुलना में काफी सीमित रहा। अफ्रीका के घाना में "Rural LPG Promotion Programme" 2013 में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की पहुंच बढ़ाना था, लेकिन वितरण नेटवर्क और सब्सिडी प्रबंधन की समस्याओं के कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके विपरीत, भारत में उज्ज्वला योजना ने राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित वितरण प्रणाली स्थापित की, जिसमें सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) और डिजिटल DBT (Direct Benefit Transfer) मॉडल का संयोजन शामिल था। यह मॉडल पारदर्शिता और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने में कारगर सिद्ध हुआ। हालाँकि, इंडोनेशिया का “Kerosene-to-LPG Conversion Program” एक ऐसा उदाहरण है जिसने स्थायी उपयोग सुनिश्चित करने में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया। वहाँ सरकार ने रिफिल सब्सिडी को लंबी अवधि तक बनाए रखा और उपभोक्ताओं के लिए डिलीवरी लागत को भी कम किया। भारत में यदि रिफिल दर को उच्च बनाए रखना है तो इंडोनेशिया की तरह सब्सिडी का दीर्घकालिक रोडमैप अपनाना उपयोगी हो सकता है।

10. चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

योजना के सफल कार्यान्वयन के बावजूद कई प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। पहली चुनौती रिफिल दर में स्थिरता है। कई लाभार्थी पहले कनेक्शन के बाद उच्च एलपीजी कीमतों के कारण पुनः ठोस ईंधन की ओर लौट जाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 10-12% उज्ज्वला लाभार्थियों ने पिछले वर्ष में एक भी रिफिल नहीं लिया। दूसरी चुनौती वितरण नेटवर्क की असमानता है। पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में सिलेंडर आपूर्ति में देरी और परिवहन लागत अधिक होने के कारण उपयोग कम है।

तीसरी चुनौती जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन से जुड़ी है। कई लाभार्थी ठोस ईंधन को सांस्कृतिक आदत, स्वाद या खाना पकाने की शैली के कारण प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा, धोखाधड़ी और फर्जी लाभार्थी सूची का मुद्दा भी सामने आया है। जुलाई 2025 में उज्ज्वला योजना में ट्रांसफर प्रक्रिया में अनियमितताओं का मामला सामने आया, जिसमें 2 लाख से अधिक कनेक्शनों में नाम बदलने की शिकायत हुई और ऑडिट

के आदेश दिए गए। इन चुनौतियों के समाधान के लिए वित्तीय, लॉजिस्टिक और सामाजिक-व्यवहारिक तीनों स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है।

11. नीति सुझाव

1. दीर्घकालिक सब्सिडी रणनीति - रिफिल लागत को कम करने के लिए इंडोनेशिया जैसे देशों के उदाहरण से प्रेरणा लेकर एक स्थायी सब्सिडी ढांचा तैयार किया जाए।
2. वितरण अवसंरचना का विस्तार - दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में एलपीजी वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और मोबाइल रिफिल वैन का प्रावधान किया जाए।
3. व्यवहार परिवर्तन अभियान - जागरूकता कार्यक्रमों में स्थानीय भाषा, सांस्कृतिक संदर्भ और महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाए ताकि लाभार्थी स्थायी रूप से एलपीजी को अपनाएँ।
4. फर्जी लाभार्थियों की रोकथाम - आधार और बैंक खाता सत्यापन के साथ-साथ थर्ड-पार्टी ऑडिट को अनिवार्य बनाया जाए।
5. पूरक नीतियाँ - एलपीजी उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ, उन्नत चूल्हा तकनीक (Improved Biomass Cookstoves) को भी बैकअप विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाए ताकि ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे।

12. निष्कर्ष

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना भारत में ऊर्जा गरीबी से निपटने के सबसे बड़े और प्रभावी प्रयासों में से एक है। इसने न केवल 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन प्रदान किया, बल्कि महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुधार और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तथापि, योजना की दीर्घकालिक सफलता इस पर निर्भर करेगी कि लाभार्थी कितनी निरंतरता से एलपीजी का उपयोग करते हैं। इसके लिए आर्थिक वहनीयता, वितरण नेटवर्क की मजबूती और सांस्कृतिक व्यवहार में परिवर्तन अनिवार्य हैं। यदि नीति निर्माता सब्सिडी, वितरण और जागरूकता को संतुलित तरीके से लागू करते हैं, तो PMUY भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का एक स्थायी मॉडल बन सकता है और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

संदर्भ

1. Ministry of Petroleum & Natural Gas. (2024). Pradhan Mantri Ujjwala Yojana - Progress Report. Government of India.
2. Press Information Bureau. (2023-2025). Various Press Releases on PMUY. Government of India.
3. Smith, K. R. (2000). Indoor air pollution and health. WHO Bulletin, 78(9), 1078-1092.

4. Kumar, N., & Singh, S. (2014). Energy Poverty in Rural India: Policy Implications. Energy Policy Journal, 67, 336-344.
5. Gould, C. F., & Urpelainen, J. (2018). LPG adoption and the PMUY in India. Energy for Sustainable Development, 46, 23-30.
6. International Energy Agency. (2021). Clean Cooking: Energy Access Outlook. Paris: IEA.
7. Asharaf, S., & Tol, R. (2024). Assessing the impact of PMUY on LPG usage. arXiv preprint arXiv:2403.17112.
8. National Statistical Office. (2023). Household Consumption of Energy in India. Government of India.
9. Navbharat Times. (2025, July). Ujjwala Yojana big scam reported in Madhya Pradesh.
10. Indonesia Ministry of Energy. (2018). Kerosene-to-LPG Conversion Program Impact Study. Jakarta: Government of Indonesia.
11. Bangladesh Clean Cooking Alliance. (2020). Annual Progress Report. Dhaka.